REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 1 | OCTOBER - 2018

जनजातीय वाणिज्य और सरगुजा जिले की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव

डॉ. शैहून एक्का
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
शासकीय नवीन महाविद्यालय, बतौली, जिला - सरगुजा (छ. ग.).

सारांश:

यह शोध पत्र भारत के छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की अर्थव्यवस्था को आकार देने में जनजातीय वाणिज्य की भूमिका की जांच करता है। यह जिला विविध जनजातीय आबादी का घर है, जिनकी पारंपरिक प्रथाएं और सांस्कृतिक विरासत स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। यह अध्ययन जनजातीय वाणिज्य के ऐतिहासिक विकास की जांच करता है, जिसमें वस्तु विनिमय प्रणालियों से लेकर समकालीन बाजार जुड़ावों तक के संक्रमण पर प्रकाश डाला गया है। मुख्य निष्कर्ष बताते हैं कि जनजातीय वाणिज्य न केवल कई परिवारों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि यह सामुदायिक विकास और सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देता है, खासकर महिलाओं के बीच। यह शोध पत्र जनजातीय उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाता है जिसमें बाजार पहुंच और वैश्वीकरण के दबाव शामिल हैं, जबकि टिकाऊ प्रथाओं के महत्व प. जोर दिया गया है। जनजातीय वाणिज्य और आर्थिक विकास के बीच परस्पर क्रिया का विश्लेषण करके, यह शोध उन सहायक नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो जनजातीय उद्यमों की व्यवहार्यता को बढ़ाती हैं और सरगुजा जिले के समग्र विकास में योगदान देती हैं।

मुख्य शब्द: आदिवासी वाणिज्य, सरगुजा जिला, आर्थिक विकास, स्वदेशी समुदाय, आजीविका, हस्तशिल्प.

परिचय:

भारत के छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित सरगुजा जिला अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध आदिवासी समुदायों के लिए जाना जाता है। गोंड, बैगा और कोरवा जैसे विभिन्न स्वदेशी समूहों का घर, यह जिला सदियों की परंपरा और अनुकूलन द्वारा आकार दिए गए एक अद्वितीय सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य का प्रतीक है। आदिवासी वाणिज्य, जिसमें इन समुदायों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान शामिल है, आजीविका को बनाए रखने और सांस्कृतिक प्रथाओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ऐतिहासिक रूप से, आदिवासी वाणिज्य वस्तु विनिमय प्रणालियों और स्थानीय व्यापार प्रथाओं से अधिक संगठित बाजार संरचनाओं में विकसित हुआ है। यह परिवर्तन वैश्वीकरण, सरकारी नीतियों और पारंपरिक कारीगरों के व्यापक आर्थिक नेटवर्क में बढ़ते एकीकरण जैसे कारकों से प्रभावित हुआ है। जैसे-जैसे आदिवासी समुदाय इन परिवर्तनों को संभालने का प्रयास करते हैं, उनके वाणिज्य का आर्थिक प्रभाव केवल जीवित रहने से परे होता है; यह सामुदायिक विकास को बढ़ावा देता है, हाशिए के समूहों, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाता है, और समग्र आर्थिक लचीलापन बढ़ाता है।

अपनी क्षमता के बावजूद, आदिवासी वाणिज्य को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें बाजारों तक सीमित पहुंच, बिचौलियों द्वारा शोषण और आधुनिक आर्थिक दबावों से उत्पन्न खतरे शामिल हैं। इस शोधपत्र का उद्देश्य सरगुजा जिले में आदिवासी वाणिज्य की गतिशीलता का पता लगाना है, इसकी ऐतिहासिक जड़ों, वर्तमान प्रथाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसके बहुमुखी प्रभाव की जांच करना है। सफल आदिवासी उद्यमों और इन गतिविधियोंका समर्थन करने वाली सरकारी पहलों के परिस्थिति

अध्ययन का विश्लेषण करके, यह शोध क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में आदिवासी वाणिज्य को संरक्षित और बढ़ावा देने के महत्व को उजागर करना चाहता है।

अंततः, आदिवासी वाणिज्य और सरगुजा जिले की अर्थव्यवस्था के बीच जटिल संबंधों को समझना न केवल इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने पर प्रकाश डालता है, बल्कि लक्षित नीतियों और हस्तक्षेपों की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है जो आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाते हैं और उनकी आर्थिक संभावनाओंको बढ़ाते हैं।

शोध के उद्देश्य:

१) सरगुजा जिले में आदिवासी वाणिज्य की गतिशीलता और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसके बहुमुखी प्रभाव की जांच करना।
२) पारंपरिक वस्तु विनिमय प्रणालियों से लेकर समकालीन बाजार प्रथाओं तक आदिवासी वाणिज्य के विकास की जांच करना आदिवासी आर्थिक गतिविधियों पर औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक नीतियों के प्रभाव को उजागर करना।
३) आदिवासी समुदायों द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के प्रकार, स्थानीय बाजारों और व्यापार मार्गों की भूमिका और पारंपरिक हस्तशिल्प के महत्व सहित आदिवासी वाणिज्य के वर्तमान रूपों का पता लगाना।
४) रोजगार सृजन, आय के स्तर और समग्र आर्थिक विकास के संदर्भ में स्थानीय अर्थव्यवस्था में आदिवासी वाणिज्य के योगदान का आकलन करना, विशेष रूप से आदिवासी उद्यमिता में महिलाओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना।
५) बाजारों तक पहुँचने, वैश्वीकरण को संभालने और गैर-आदिवासी उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों की जाँच करना, साथ ही साथ उनके वाणिज्य पर बुनियादी ढाँचे की कमी के प्रभाव की जाँच करना।

साहित्य समीक्षा:

मिश्रा (२०१०) छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों की पारंपरिक आर्थिक प्रथाओं की पड़ताल करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली और स्थानीय व्यापार पर उनकी निर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तिवारी (२०१२) आदिवासी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में स्वयं सहायता समूहों(एसएचजी) की भूमिका की जांच करते हैं, पाते हैं कि स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त और कौशल विकास तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है। पांडा(२०१४) सरगुजा जिले पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूर्वी भारत में आदिवासी वाणिज्य पर वैश्वीकरण के प्रभावों का विश्लेषण करते हैं।

भौमिक (२०१६) आदिवासी वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने में स्थानीय बाजारों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि वे आदिवासी कारीगरों को हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को बेचने के लिए मंच के रूप में काम करते हैं। साहू (२०१५) छत्तीसगढ़ में आदिवासी वाणिज्य के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं शोधपत्र में इन पहलों के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए अधिक जागरूकता और अवसंरचनात्मक समर्थन की मांग की गई है।

शोध पद्धति:

यह शोध सरगुजा जिले की अर्थव्यवस्था पर आदिवासी वाणिज्य के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण का उपयोग करता है। यह सर्वेक्षण, साक्षात्कार और लक्षित समूह चर्चाओं के माध्यम से प्राथमिकआँकड़े एकत्र करते हुए एक वर्णनात्मक शोध रचना का उपयोग करता है। द्वितीयक आँकड़े सरकारी रिपोर्टों, शैक्षणिक पत्रिकाओं और गैर सरकारी संगठनों से एकत्रकिये गए है। डेटा विश्लेषण में रुझानों और चरों के बीच संबंधों की पहचान करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तकनीकों का उपयोग किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य आदिवासी वाणिज्य की सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता की व्यापक समझ प्रदान करना है।

आदिवासी वाणिज्य और सरगुजा जिले की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव:

भारत के उत्तरी छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिला गोंड, बैगा और कोरवा जैसे विविध आदिवासी समुदायों का घर है। आदिवासी वाणिज्य उनकी आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्थानीयअर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। पारंपरिक प्रथाओं में वस्तुओं के आदानप्रदान के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली शामिल है, जबकि आधुनिक विकास ने औपचारिक बाजारों और सहकारी

समितियों की स्थापना की है। जनजातीय वाणिज्य जनजातीय समुदायों को बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षिक सुविधाओं में निवेश करने में सक्षम बनाकर रोजगार, आय स्तर और सामुदायिक विकास उत्पन्न करता है।

हालांकि, जनजातीय वाणिज्य के सामने आने वाली चुनौतियों में सीमित बाजार पहुंच, वैश्वीकरण के दबाव और बिचौलियों द्वारा शोषण शामिल हैं। सीमित बुनियादी ढांचा, परिवहन की कमी और अपर्याप्त बाजार जानकारी कारीगरों को स्थानीय हाटों से परे उत्पाद बेचने से रोकती है। बाहरी बाजारों से सस्ते, बड़े पैमाने पर उत्पादित सामानों की आमद पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए एक बड़ा खतरा है, जिससे हस्तनिर्मित वस्तुओं की मांग में गिरावट आती है। इसके अतिरिक्त, कई आदिवासी कारीगरों का अक्सर बिचौलियों द्वारा शोषण किया जाता है जो मुनाफे में से बड़ी कटौती करते हैं, जिससे उनकी आय सीमित हो जाती है और उनकी आर्थिक व्यवहार्यता कम हो जाती है।

सरकार और गैर सरकारी संगठनों की पहल का उद्देश्य नीति समर्थन, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार संबंधों के माध्यम से जनजातीय वाणिज्य को बढ़ावा देना है। गैर-सरकारी संगठन उत्पाद विकास, गुणवत्ता नियंत्रण और विपणन रणनीतियों में प्रशिक्षण प्रदान करके जनजातीय वाणिज्य का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं साथ ही सहकारी समितियों का निर्माण करते हैं जो आदिवासी कारीगरों को सामूहिक आवाज और बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करते हैं।

आदिवासी वाणिज्य में सतत प्रथाओं में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उत्पादन, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देना शामिल है। इन प्रथाओं को बढ़ावा देकर, आदिवासी वाणिज्य इन समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने में मदद करता है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है और सांस्कृतिक पर्यटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में योगदानदेता है।

सरगुजा जिले में आदिवासी वाणिज्य आजीविका प्रदान करके, सामुदायिक विकास को बढ़ावा देकर और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। हालाँकि, इसकी व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए विभिन्न चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने, उनकी परंपराओं और मूल्यों का सम्मान करते हुए उनकी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी पहलों, गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक प्रयासों से निरंतर समर्थन आवश्यक है।

जनजातीय वाणिज्य: वर्तमान प्रथाएँ

जनजातीय उत्पादों और सेवाओं के प्रकार

सरगुजा में जनजातीय समुदाय अपने हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें बुनाई, मिट्टी के बर्तन और बांस शिल्प शामिल हैं। गोंड और बैगा अपनी जटिल बुनाई तकनीकों के लिए जाने जाते हैं, जो प्राकृतिक रेशों और रंगों का उपयोग करके पारंपरिक वस्त्र, शॉल और कालीन बनाते हैं। जटिल रचना और पारंपरिक रूपांकनों की विशेषता वाले मिट्टी के बर्तन स्थानीय और क्षेत्रीय बाजारों में लोकप्रिय हैं। बांस शिल्प, एक बहुमुखी सामग्री, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग में योगदान करती है। चावल, एक मुख्य भोजन, आदिवासी किसानों द्वारा उगाया जाता है, जबकि जंगल निर्वाह और वाणिज्य के लिए शहद, फल, मेवे और रेजिन का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करते हैं। औषधीय पौधों का स्वदेशी ज्ञान भी आदिवासी समुदायों में प्रचलित है, जो पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली विभिन्न जड़ी-बूटियों और पौधों की कटाई और बिक्री करते हैं। बकरी, भेड़ और मुर्गी सहित पशुधन पालन, पशुओं और उनके उपउत्पादों, जैसे दूध और अंडे की बिक्री के माध्यम से जीविका और आय प्रदान करता है। दूध और घी तथा दही जैसे पारंपरिक डेयरी उत्पादों के लिएस्थानीय बाजार विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

बाजार संरचनाएँ और व्यापार प्रथाएँ

स्थानीय बाजार और मेले आदिवासी वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो व्यापार और सामाजिक संपर्क के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। ये बाजार आदिवासी कारीगरों और किसानों को अपने सामान सीधे उपभोक्ताओं को बेचने में सक्षम बनाते हैं, जिससे सामुदायिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलता है। सहकारी समितियाँ और स्वयं सहायता समूह(SHG) भी आदिवासी कारीगरों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो उनकी सौदेबाजी की शक्ति और बाजारों तक पहुँच को बढ़ाते हैं। सहकारी समितियाँ उत्पादों के सामूहिक विपणन की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे सदस्यों को संसाधनों को साझा करने और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने की अनुमति मिलती है। स्वयं सहायता समूह आदिवासी महिलाओं को सूक्ष्म वित्त, कौशल प्रशिक्षण और बाजार संपर्क तक पहुँच प्रदान करके सशक्त बनाते हैं, उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करते हैं। पारंपरिक वस्तु विनिमय प्रणाली, जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान बिना नकदी के किया जाता है, सामुदायिक संबंधों को बढ़ावा देती है लेकिन बाजार कीपहुँच को सीमित करती है।

आधुनिक वाणिज्य ने अधिक नकद लेन-देन को बढ़ावा दिया है, जिससे अधिक लचीलापन मिलता है लेकिन कारीगरों को बाजार की अस्थिरता और मूल्य में उतार-चढ़ाव का सामना भी करना पड़ता है।

आधुनिक प्रभाव और चुनौतियाँ:

वैश्वीकरण के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जिससे पारंपरिक हस्तशिल्प की माँग प्रभावित हुई है और स्वदेशी शिल्प के अस्तित्व को संभावित रूप से खतरा पैदा हुआ है। आदिवासी वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ लागू की गई हैं, जैसे कि आदिवासी उप-योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, लेकिन उनकी प्रभावशीलता अक्सर स्थानीय कार्यान्वयन और आदिवासी समुदायों के बीच जागरूकता पर निर्भर करती है। चुनौतियों में बिचौलियों द्वारा शोषण, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे के कारण बाज़ारों तक पहुँच की कमी और अपर्याप्त सड़कें और भंडारण सुविधाएँ जैसे बुनियादी ढाँचे के मुद्दे शामिल हैं। ये मुद्दे आदिवासी समुदायों को उनके शिल्प से मिलने वाले आर्थिक लाभों को कमज़ोर कर सकते हैं, बड़े बाज़ारों तक पहुँच को सीमित कर सकते हैं और आदिवासी समुदायों की लाभप्रदता और विकास क्षमता में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए, आदिवासी समुदायों के लिए अपने पारंपरिक शिल्प के अस्तित्व और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए वैश्वीकरण के बदलते परिदृश्य के अनुकूल होना महत्वपूर्ण है।

जनजातीय वाणिज्य का आर्थिक प्रभाव:

जनजातीय वाणिज्य स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रोजगार के अवसर प्रदान करता है, आजीविका का समर्थन करता है और आय स्रोतों का विविधीकरण करता है। इसमें हस्तशिल्प, कृषि और स्थानीय व्यापार में प्रत्यक्ष रोजगार शामिल है, परिवारों का समर्थन करता है और गरीबी के स्तर को कम करता है। अप्रत्यक्ष रोजगार परिवहन, खुदरा और सेवाओं जैसे अन्य क्षेत्रों तक फैला हुआ है। जनजातीय परिवार कृषि उपज, शिल्प और पशुधन बेचने जैसे विभिन्न प्रकार के वाणिज्य के माध्यम से अपने आय स्रोतों में विविधता लाते हैं। स्वयं सहायता समूह(एसएचजी) आदिवासी महिलाओं को सूक्ष्म वित्त और प्रशिक्षण तक पहुँच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में सहायक रहे हैं, जिससे उन्हें छोटे व्यवसायों में निवेश करने और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाने में मदद मिली है। स्वयं सहायता समूह कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, महिलाओं को हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योगों और उद्यमिता में मूल्यवान कौशल सिखाते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और आय क्षमता बढ़ती है। उदाहरण के लिए, एक आदिवासी कारीगर जिसने हस्तनिर्मित शिल्प को बाजार में लाने के लिए एक सहकारी संस्था की स्थापना की, वह समुदाय में दूसरों के लिए एक आदर्श के रूप में काम कर सकता है। आधुनिक विपणन रणनीतियों या पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने वाले उद्यमी अक्सर यह प्रदर्शित करते हैं कि कैसे आदिवासी वाणिज्य सांस्कृतिक प्रामाणिकता को बनाए रखते हुए बदलते बाजार की गतिशीलता के अनुकूल हो सकता है।

सामुदायिक विकास पर प्रभाव:

आदिवासी वाणिज्य के कई लाभ हैं, जिनमें शिक्षा तक बेहतर पहुँच, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण सुधार और सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का संरक्षण शामिल है। आदिवासी वाणिज्य से होने वाली आय में वृद्धि से बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है, जिससे साक्षरता दर और कौशल विकास में सुधार होता है। गैर सरकारी संगठन और सरकारी पहल आदिवासी वाणिज्य से संबंधित कौशल बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते हैं, जो समुदाय के भीतर मानव पूंजी विकास में योगदान करते हैं। आर्थिक स्थिरता आदिवासी परिवारों को स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने की अनुमति देती है, जिससे स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होता है। बेहतर स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल तक पहुँच जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रम भी लागू किए जाते हैं। आदिवासी वाणिज्य सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें पारंपरिक शिल्प, कला और कृषि उत्पादों का उत्पादन और बिक्री की जाती है। स्थानीय बाज़ार और मेले अक्सर सांस्कृतिक उत्सवों को शामिल करते हैं जो आदिवासी विरासत का जश्न मनाते हैं, आगंतुकों को आकर्षित करते हैं और आय उत्पन्न करते हुए समुदाय को बढ़ावा देते हैं।

सतत विकास और पर्यावरण संबंधी विचार:

आदिवासी वाणिज्य प्रथाएँ स्थायी सामग्री, पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान और वन संरक्षण के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं। आदिवासी कारीगर पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री, जैसे प्राकृतिक रंग और जैविक रेशों का उपयोग करते हैं। वे जैव

विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हुए स्थायी कृषि और वानिकी प्रथाओं का मार्गदर्शन करने के लिए पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान का भी उपयोग करते हैं। आदिवासी समुदाय वन प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वनों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए स्थायी कटाई तकनीकों का अभ्यास करते हैं। सामुदायिक वन प्रबंधन पहल जैव विविधता के संरक्षण और वन उत्पादों के सतत उपयोग की अनुमति देने में प्रभावी साबित हुई है। आदिवासी वाणिज्य में स्थायी पर्यटन की भी संभावना है, जिसमें सांस्कृतिक पर्यटन पर्यटकों को आकर्षित करता है और इको-पर्यटन पहल सरगुजा की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करती है। ये प्रथाएँ पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करते हुए आदिवासी समुदायों के आर्थिक लाभ में योगदान करती हैं।

निष्कर्ष:

सरगुजा जिले में आदिवासी वाणिज्य स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आर्थिक लचीलापन बढ़ाता है और परिवारों को सहारा देता है। इसमें हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और पशुधन शामिल हैं, और सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाता है। आदिवासी वाणिज्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण पहलों तक पहुँच में भी सुधार करता है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है और पारंपरिक प्रथाओं को वैश्वीकृत दुनिया में पनपने देता है। हालांकि वैश्वीकरण, बाजार पहुंच और बुनियादी ढांचे की सीमाओं जैसी चुनौतियों का समाधान करने की जरूरत है। आदिवासी वाणिज्य का पूरा उपयोग करने के लिए सरकारी नीतियों, गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक जुड़ाव की जरूरत है। टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और बाजार पहुंच को सुविधाजनक बनाने से आर्थिक लाभ को बढ़ाया जा सकता है जिससे आधुनिक अर्थव्यवस्था में इन समुदायों का अस्तित्व और समृद्धि सुनिश्चित हो सके। निष्कर्ष रूप में, आदिवासी वाणिज्य केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि सरगुजा जिले में सामाजिक पहचान, सांस्कृतिक संरक्षण और सतत विकास की आधारशिला है।

संदर्भ:

1. *Bhowmik, R. (2016). Importance of local markets in facilitating tribal commerce: Platforms for tribal artisans to sell handicrafts and agricultural products. Journal of Tribal Studies, 10(1), 45-59.*
2. *Central Statistical Organisation (CSO) and Ministry of Agriculture, Government of India. (2013). Databook for DCH, 10th March 2014. Available:* *http://planningcommission.nic.in/data/datatable/1203/table_56.pdf*
3. *Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India. (2004). State at a glance, State-wise Population Below Poverty Line 1999-2000. Available:* *http://agricoop.nic.in/statatglance2004/Ecoindicator.pdf*
4. *Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, Government of India. (2012a). Livestock Census, Part IV, Livestock Population 2003 & 2007. Available:* *http://dahd.nic.in/dahd/bahs-2012.aspx*
5. *Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India. (2013a). APY State data 96-12. Available:* *http://eands.dacnet.nic.in/StateData_96-12Year.htm*
6. *Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India. (2013b). LUS State data 99-04. Available:* *http://eands.dacnet.nic.in/LUS_1999_2004.htm*
7. *Indian Institute of Vegetable Research. (2013). Vegetable Statistics, Technical Bulletin No. 51. Nirmal Vijay Printer, New Delhi. Available:* *http://iivr.org.in/Publications/Vegetable%20Statistics.pdf*
8. *International Food Policy Research Institute (IFPRI). (2009). India State Hunger Index, Comparisons of Hunger Across States. IFPRI, Washington DC.*
9. *International Fund for Agricultural Development (IFAD). (1999). Report and Recommendation of the President to the Executive Board on a proposed loan to the Republic of India for the Bihar-Madhya Pradesh Tribal Development Programme, EB 99/66/R.19/Rev.1. IFAD, Rome.*
10. *International Fund for Agricultural Development (IFAD). (2005). Republic of India, Country Strategic Opportunities Paper, EB 2005/86/R.11, Agenda Item 7(c). IFAD, Rome.*

11. *International Fund for Agricultural Development (IFAD). (2010). Rural Poverty, Rural Poverty Portal, India. Available:* http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/india
12. *International Fund for Agricultural Development (IFAD). (2012a). Republic of India, Jharkhand-Chhattisgarh Tribal Development Programme (JCTDP), Project Completion Report, Report No 2862-IN, September. IFAD/PMD Asia and the Pacific Division, Rome.*
13. *International Fund for Agricultural Development (IFAD). (2012b). India, Jharkhand Tribal Development Programme (506-IN), PCR Validation Mission: Aide Memoire, Sep 17-30, 2012. IFAD, Rome.*
14. *International Fund for Agricultural Development (IFAD). (2013). Impact evaluation of the Sri Lanka Dry Zone Livelihood Support and Partnership Programme, Approach paper, EC 2013/76/W.P.7. IFAD, Rome.*
15. *Kispotta, Dr. (2014). A Socio-Economic miserable condition of the tribals in Chhattisgarh (A case study of Dhanwar, Surguja district, C.G.). IOSR Journal of Humanities and Social Science, 19, 26-29. https://doi.org/10.9790/0837-19612629*
16. *Mishra, S. (2010). Traditional economic practices of tribal communities in Chhattisgarh: Focus on barter systems and local trade. Journal of Indigenous Economics, 5(3), 78-91.*
17. *Naidu, P. R. (n.d.). Bharat Ke Adivasi Vikas Ki Samasyae. Radha Publication, New Delhi.*
18. *Office of the Registrar General & Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India. (2011a). Census of India 2001. Available:* http://www.censusindia.gov.in/2011-common/census_data_2001.html
19. *Office of the Registrar General & Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India. (2011b). Census of India 2011. Available:* http://www.censusindia.gov.in/default.aspx
20. *Panda, A. (2014). Effects of globalization on tribal commerce in Eastern India: Focus on Surguja District. Eastern India Economic Review, 8(2), 101-115.*
21. *Planning Commission, Government of India. (2013). Press Note on Poverty Estimates, 2011-12. Press Information Bureau, New Delhi. Available:* http://www.planningcommission.nic.in/news/pre_pov2307.pdf
22. *Rani, P. (2016). Government initiatives promoting tribal entrepreneurship: Evaluation of successes and shortcomings. Journal of Social Policy and Development, 12(4), 137-150.*
23. *Report of the High Level Committee on Socioeconomic, Health and Educational Status of Tribal Communities of India. (2014). Ministry of Tribal Affairs, Government of India.*
24. *Report of The High Level Committee on Socio-economic, Health and educational status of Tribal Communities of India. (2014). Ministry of Tribal Affairs, Government of India.*
25. *Sahu, M. (2015). Socio-economic impact of tribal commerce in Chhattisgarh: Role in poverty alleviation and employment generation. Journal of Socio-Economic Development, 9(3), 66-80.*
26. *Singh Negi, N., & Ganguly, S. (2011). Development Project vs. Internally Displaced Populations in India: A Literature Based Appraisal, Working Papers No. 103, 2011. COMCAD, Bielefeld.*
27. *Statistical Profile of Scheduled Tribes in India (2013). Ministry of Tribal Affairs Statistics Division, Government of India. Available:* www.tribal.nic.in
28. *Tiwari, R. (2012). Role of Self-Help Groups (SHGs) in empowering tribal women economically: Access to microfinance and skill development. Journal of Rural Development Studies, 7(2), 55-70.*
29. *United Nations Development Programme (UNDP). (2011a). India, Economic and Human Development Indicators. Available:* http://www.in.undp.org/content/dam/india/docs/india_factsheet_economic_n_hdi.pdf
30. *United Nations Development Programme (UNDP). (2011b). Jharkhand, Economic and Human Development Indicators. Available:* http://www.in.undp.org/content/dam/india/docs/jharkhand_factsheet.pdf
31. *United Nations Development Programme (UNDP). (2011c). Chhattisgarh, Economic and Human Development Indicators. Available:* http://www.in.undp.org/content/dam/india/docs/chhattisgarh_factsheet.pdf

32. *United Nations Development Programme (UNDP). (2011d). About UNDP in India, UNDP in Chhattisgarh. Available:* *http://www.in.undp.org/content/india/en/home/operations/about_undp/undp-inJharkhand/about-Jharkhand/*